



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 168

दि. 23.03.2026,

रविवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाई वैश्विक चिंता, नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी—“दुनिया एकजुट हो, खतरा अब सीमाओं से परे”

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में लगातार गहराते संकट के बीच इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बढ़ते टकराव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह संघर्ष अब केवल इजरायल और ईरान के बीच का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। अरब शहर के दौरे के दौरान नेतन्याहू ने हालिया मिसाइल हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि Iran ने जानबूझकर

रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में हुए हमलों में नागरिक क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर व्यापक तबाही मचाने की कोशिश की गई, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। उनके अनुसार, इन हमलों का उद्देश्य केवल सैन्य दबाव बनाना नहीं, बल्कि आम जनता में भय और अस्थिरता फैलाना भी था। नेतन्याहू ने विशेष रूप से ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब ऐसी मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, जिनकी मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर तक है। इस दायरे में न केवल इजरायल बल्कि यूरोप के कई देश भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह खतरा अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि



वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उनके शब्दों में, “आज जो खतरा इजरायल के सामने है, कल वही खतरा दुनिया के किसी भी हिस्से में दिखाई दे सकता है।” प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया

कि हालिया हमलों के दौरान यरुशलम के अत्यंत पवित्र और संवेदनशील धार्मिक स्थलों के आसपास मिसाइलों गिरें। उन्होंने कहा कि Western Wall, Church of the Holy Sepulchre और Al-Aqsa

Mosque जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों के बेहद करीब हमले हुए, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। उन्होंने इसे न केवल सैन्य बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर भी हमला बताया। नेतन्याहू ने इस दौरान Donald Trump को उस अपील का समर्थन किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ईरान के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया था। उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका मिलकर केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह लड़ाई आतंक और अस्थिरता के खिलाफ है, जिसे वैश्विक सहयोग के बिना नहीं जीता जा सकता। इस बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने

अपने दो प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य भी स्पष्ट कर दिए हैं। पहला, ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करना, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े खतरे को रोका जा सके। दूसरा, ईरान के भीतर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, जिससे वहां की जनता मौजूदा शासन के खिलाफ खड़ी हो सके और एक स्थिर एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, हालिया हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। अरब और डिमोन जैसे शहरों में हुए हमलों में कुल 175 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पतालों में आपात स्थिति बनी हुई है और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। इन घटनाओं ने आम नागरिकों

के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। कई देशों ने संयम बरतने और तत्काल संवाद की पहल करने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टकराव और बढ़ता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं के भीतर नहीं रहते, बल्कि उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला

में बाधा, और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे पहले से ही वैश्विक चिंता बने हुए हैं, ऐसे में यह नया संघर्ष स्थिति को और जटिल बना सकता है। नेतन्याहू की अपील और चेतावनी इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दिशा इस संकट से प्रभावित होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्विक समुदाय इस चुनौती का सामना किस तरह करता है—क्या वे एकजुट होकर समाधान की दिशा में बढ़ते हैं या यह टकराव और गहराता चला जाता है। फिलहाल, पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हैं, जहां हर नया घटनाक्रम वैश्विक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

‘बापू सभागार से उठा संकल्प: सांस्कृतिक जागरण के साथ विकसित बिहार की ओर बढ़ता कदम’

(जीएनएस)। पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में रविवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने न केवल उपस्थित हजारों लोगों को भावुक किया, बल्कि बिहार के भविष्य की एक नई तस्वीर भी सामने रख दी। ‘लेट्स इम्प्यार बिहार’ अभियान के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित यह भव्य समारोह अपने आप में एक जनांदोलन का रूप लेता नजर आया, जहां संस्कृति, शिक्षा, तकनीक और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ मंच पर दिखाई दी। करीब 5,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि अब बिहार का समाज केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह खुद अपने विकास की कहानी लिखने के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे विकास वैभव, जिन्होंने अपने उद्घोषण में अभियान की अवतक की यात्रा को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे छोटे से विचार के रूप में शुरू हुआ यह अभियान आज लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चौथी वर्षगांठ तक जहां 1.85 लाख लोग इस अभियान से जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 3.55 लाख हो चुकी है। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं, बल्कि

समाज में बढ़ती जागरूकता, भागीदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने उपस्थित जनसमुह से आह्वान किया कि आने वाले वर्ष में इस अभियान से 10 लाख लोगों को जोड़कर इसे एक सशक्त सामाजिक क्रांति का रूप दिया जाए। विकास वैभव ने अपने संबोधन में बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी गहराई से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है, जहां से ज्ञान और विचार की ऐसी धारा निकली, जिसने पूरे विश्व को दिशा दी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र आज भी इस बात के साक्ष्य हैं कि बिहार कभी विश्व का बौद्धिक केंद्र रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जरूरत है उस गौरवशाली अतीत को आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ जोड़कर भविष्य की नई इबारत लिखने की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने केवल भाषण ही नहीं सुने, बल्कि एक सामूहिक संकल्प भी लिया। सभागार में खड़े होकर हजारों लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे बिहार को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका

निभाएंगे। अतिथिगणित एंजेलिजेंस, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। यह संकल्प इस बात का प्रतीक था कि अब बिहार का विकास केवल नीतियों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि जनता की सहभागिता से ही इसे गति मिलेगी। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, पत्रकार और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम का संचालन अनुप नारायण सिंह, डॉ. शिवनम अखौरी और श्वेता सुरभी ने बेहद प्रभावी तरीके से किया, जिससे पूरे आयोजन में ऊर्जा और निरंतरता बनी रही। मंच पर परमहंस स्वामी आपामानंद महाराज और विनय भाई पात्रले सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमायुक्त उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रतिष्ठित बना दिया। इन सभी वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि बिहार का पुनर्जागरण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरे समाज का सामूहिक कर्तव्य है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जिससे यह संदेश रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। यह उतना ही जरूरी है। इससे युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। पूरे आयोजन के दौरान एक बात बार-बार सामने आई कि ‘लेट्स इम्प्यार बिहार’ अब केवल एक अभियान नहीं रहा, बल्कि यह एक विचारधारा बन चुका है। यह विचारधारा समाज को जोड़ने, जागरूक करने और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हजारों लोग एक साथ खड़े होकर बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए संकल्प ले रहे थे, तो वह दृश्य किसी आंदोलन से कम नहीं लग रहा था। यह आयोजन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार अब अपने अतीत की महानता को आधार बनाकर भविष्य की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। यदि इसी तरह समाज, नेतृत्व और युवाओं की ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार न केवल भारत, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विकास, नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि का उदाहरण बनेगा।

होर्मुज पर नरमी से बदला समीकरण, ईरान का आंशिक खुला ऐलान वैश्विक ऊर्जा बाजार को मिली राहत, तनाव अब भी बरकरार

(जीएनएस)। नई दिल्ली/तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीववरक्षा माने जाने वाले Strait of Hormuz को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। Iran ने अपने रुख में आंशिक नरमी दिखाते हुए घोषणा की है कि दुश्मन देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों के जहाज इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजर सकते हैं। इस फैसले को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए राहत भरा संकेत माना जा रहा है, हालांकि क्षेत्र में तनाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने स्पष्ट किया कि जो जहाज सीधे तौर पर United States और Israel से जुड़े नहीं हैं, वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अपने हितों और सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में Donald Trump ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे, विशेषकर पावर प्लांट्स पर



कार्रवाई कर सकता है। इस चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और गंभीर हो गई थी, क्योंकि इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है। ईरान ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने को तैयार है। हालांकि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा संकट के लिए वह अमेरिका और इजराइल के हालिया सैन्य कदमों को जिम्मेदार मानता है। ईरान का कहना है कि वह कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उस पर हो रहे हमले बंद हों और आपसी विश्वास बहाल किया जाए। दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग

20 प्रतिशत और एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का करीब 22 प्रतिशत परिवहन होता है। इस मार्ग से Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait और Iraq जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का निर्यात पूरी दुनिया तक पहुंचता है। 28 फरवरी को जब ईरान ने इस मार्ग को बंद किया था, तब वैश्विक बाजार में हलचल मच गई थी। तेल टैंकों की आवाजाही रुकने से सप्लाई चेन बाधित हो गई और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई। जहाजों की कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से इस मार्ग से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ा और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों, खासकर भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई, क्योंकि इससे महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि ईरान के इस नए फैसले से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। क्योंकि

दुश्मन देशों के जहाजों पर प्रतिबंध जारी रहने से टकराव की संभावना खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक बयानबाजी भी तनाव को लगातार बढ़ा रही हैं। वहीं NATO से जुड़े कई देशों ने इस संकट पर चिंता जताई है, लेकिन वे सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होने से बच रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वैश्विक आपूर्ति पर कोई बड़ा असर न पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी है। यहां होने वाला हर छोटा बदलाव भी पूरी दुनिया के बाजार, व्यापार और कूटनीति को प्रभावित करता है। ईरान का यह आंशिक खुलापन एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयास और आपसी विश्वास की बहाली बेहद जरूरी होगी। फिलहाल, दुनिया की नजरें इस संवेदनशील क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, जहां हर निर्णय और हर बयान वैश्विक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह नरमी स्थायी शांति की ओर पहला कदम साबित होती है या फिर यह केवल एक अस्थायी राहत बनकर रह जाती है।

‘सदन की मर्यादा पर सवाल: आतिशी की मांग-निलंबित विधायकों की बहाली से ही बचेगा लोकतांत्रिक संतुलन’

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सियासत में एक बार फिर लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी मर्यादाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर निलंबित विधायकों को तत्काल बहाल करने की मांग उठाते हुए न केवल सदन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की किसी भी कोशिश को लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना जाएगा। उनका यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब हालिया विधानसभा सत्र को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है और पक्ष-विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आतिशी ने अपने विस्तृत पत्र में कहा है कि विधानसभा केवल सरकार के निर्णयों को औपचारिक रूप देने का मंच नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि मिलकर नीतियों पर बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि विपक्ष को ही सदन से बाहर कर दिया जाएगा, तो लोकतंत्र का संतुलन स्वतः ही विगड़ जाएगा। उनके अनुसार, हालिया सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों को जिस तरह बिना ठोस कारण के निलंबित किया गया और पूरे सत्र के दौरान उन्हें सदन परिसर में प्रवेश तक नहीं दिया गया, वह न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन भी है। अपने पत्र में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम



को विस्तार से रखते हुए यह भी आरोप लगाया कि सत्रा पक्ष के कुछ सदस्यों ने लगातार तीन दिनों तक सदन की कार्यवाही को बाधित किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत विपक्ष के विधायकों पर सख्त कदम उठाए गए, जो यह दर्शाता है कि नियमों का पालन समान रूप से नहीं किया गया। आतिशी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताते हुए कहा कि यदि सदन में निष्पक्षता नहीं रहेगी, तो जनता का विश्वास भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों से वंचित करना केवल व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि उन लाखों मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को अपनी आवाज उठाने के लिए चुना है। इस प्रकार की

कार्रवाई से न केवल विधायी प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि यह लोकतंत्र की उस भावना को भी चोट पहुंचाती है, जिसमें हर आवाज को सुनने और सम्मान देने की परंपरा रही है। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए निलंबित विधायकों को आगामी बैठक में शामिल होने की अनुमति दें। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली पहचान है। यदि सदन में केवल एक पक्ष की आवाज गूंजेगी, तो वह लोकतांत्रिक मंच नहीं, बल्कि एकतरफा व्यवस्था बनकर रह जाएगा। उन्होंने अपने पत्र के अंत में यह आशा भी व्यक्त की कि विधानसभा अध्यक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं और

सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उनके अनुसार, यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा प्रश्न है, जिसका समाधान निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ ही संभव है। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या आज के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है या नहीं। यह सवाल केवल एक राज्य या एक सत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी लागू होता है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि सभी पक्ष संवाद, सहमति और पारदर्शिता के रास्ते को अपनाएं, ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनीं रहें और जनता का भरोसा कायम रह सके।



नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

